

ति एवं शक्ति एक ही व्यक्ति केवल आर्थिक दृष्टि से बलिक त रहते हैं। यहाँ आनुवंशिक भेद और भी बढ़ जाते हैं। में कई समस्याओं का सामना यों का संस्तरणात्मक प्रणाली नके लाभ के लिए योजनाएं एवं किसी भी नवीन योजना में सामाजिक, आर्थिक एवं

की प्रणाली और जातियों की
ई। साधारणतः अकृषक भू- करने वाली और दस्तकारी मेकों की जातियाँ। ग्रामीण प्रणाली में शिखर पर नहीं तुल्य सम्पन्न कृषक जातियों शक्ति को बढ़ाने में विशेष मिहीन कृषि श्रमिक आते क क्षेत्र में हो रहे परिवर्तनों धिकार तथा ग्राम पंचायतों ही शक्ति के आधार नहीं जितनी पहले कभी नहीं गई है, चाहे उनकी संख्या भू-स्वामियों—मध्यम और दृष्टि से कुछ लाभ मिला क्ष रूप से बढ़ी है, परन्तु णं आया है।

सम्बन्ध

IN INDIA)

हां की भूमि व्यवस्था पर संलग्न व्यक्तियों के बीच को समझने के लिए यहाँ

ने वाले का भूमि के प्रति प से सम्बन्ध की व्याख्या

है। दूसरे शब्दों में, यह भी कह सकते हैं कि भूमि पर स्थायी मलिकाना हक किस व्यक्ति का है? उस पर खेती वास्तव में कौन करता है? तथा उस भूमि पर लगान निर्धारित करने की नीति क्या है? यह तीनों बातें मिलकर भूमि व्यवस्था को बताती हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि **भूमि व्यवस्था से अर्थ उस व्यवस्था से है जिसके अनुसार भूमि का स्वामित्व, अधिकार एवं निर्धारित किए जाते हैं।**

एक आदर्श भूमि व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिसमें यह गुण हों—(1) भूमि पर जोतने वाले का स्वामित्व होना चाहिए। (2) लगान उचित मात्रा में लिया जाना चाहिए। (3) भूमि के हस्तान्तरण की स्वतन्त्र व्यवस्था होनी चाहिए। (4) जोतों की सीमा निर्धारित होनी चाहिए। **स्वतन्त्रता के समय भारत में भूमि व्यवस्था** (Land Tenures at the Time of Independence)

स्वतन्त्रता के समय सन् 1947 में भारत में विभिन्न प्रकार की भूमि व्यवस्था पाई जाती थीं जिनको तीन प्रमुख व्यवस्थाओं में बांटा जा सकता है—(I) रयतवारी, (II) महालवारी एवं (III) जमींदारी। ऐसा अनुमान है कि कुल कृषि क्षेत्र का 52 प्रतिशत भाग रयतवारी में 40 प्रतिशत भाग जमींदारी में व शेष महालवारी व अन्य व्यवस्थाओं में था।

(I) **रयतवारी व्यवस्था** (Ryotwari System)—इस प्रणाली में भूमि पर स्वामित्व राज्य का होता था, किन्तु व्यवहार में प्रत्येक रजिस्टर्डधारी (रयत) स्वामी होता था। जब तक वह भूमि पर राज्य को नियमित रूप से कर देता रहता था उसे बेदखल नहीं किया जा सकता था। उसको भूमि को काम में लेने, उसे बेचने या हस्तान्तरित करने या किसी अन्य प्रकार से उपयोग में लाने का अधिकार होता था। भूमि पर मालगुजारी का निर्धारण राज्य द्वारा 20-30 वर्ष के पश्चात् भूमि की उर्वरा शक्ति तथा उपज के अनुसार तय किया जाता था।

(II) **महालवारी व्यवस्था** (Mahalwari System)—इस प्रणाली में सरकार द्वारा पूरे क्षेत्र के लिए एक रकम मालगुजारी के रूप में तय कर दी जाती थी जिसको देने का उत्तरदायित्व गांवों के सभी भू-स्वामियों का होता था जिन्हें सहभागी कहते थे और महाल का अर्थ ग्राम है। चूंकि भूमि पर समस्त ग्राम का स्वामित्व होता था इसलिए इसे महालवारी व्यवस्था कहते हैं। जो भूमि गांव में खाली होती थी उस पर ग्राम समाज का अधिकार होता था। गांव का स्वतंत्र मालगुजारी एकत्रित करता था जिसके लिए उसको कमीशन मिलता था। सहभागी को अपनी इच्छानुसार भूमि को प्रयोग में लाने का अधिकार होता था। उसकी भूमि उसके परिवार की निजी सम्पत्ति मानी जाती थी। यदि कोई सहभागी उस भूमि को छोड़ देता था तो उस पर ग्राम समाज का अधिकार माना जाता था।

(III) **जमींदारी-व्यवस्था** (Zamindari System)—इस प्रणाली में जमींदार भूमि का स्वामी माना जाता था तथा भूमि सम्बन्धी सभी अधिकार उसी के हाथ में होते थे। सरकार से शर्क का सीधा सम्बन्ध नहीं होता था, बल्कि एक मध्यम वर्ग के माध्यम से होता था जिसे जमींदार कहते थे। इस प्रकार भूमि को जोतने वालों का भूमि में स्वामित्व नहीं होता था। जमींदार द्वारा उन कृषकों को हटा दिया जाता था जो कम लगान देते थे और उनकी भूमि उन व्यक्तियों को दे दी जाती थी जो अधिक लगान देते थे। इससे किसान के मन में अस्थिरता पैदा होती थी।

भूमि सुधार

(LAND REFORMS)

कृषि क्षेत्र में जहां एक ओर कुछ लोगों के पास भूमि काफी अधिक मात्रा में पाई जाती है, वहां दूसरी ओर बहुत से लोग इससे पूर्णतः वंचित हैं। परिणाम यह हुआ कि एक ओर जमींदारों और दूसरी ओर किराये पर भूमि जोतने वाले काशतकारों तथा भूमिहीन श्रमिकों के बीच असमानता की खाई बहुत बढ़ गई है। देश के स्वतन्त्र होने के पश्चात् लोगों का ध्यान असमानता के इन विपरीत छोरों की ओर गया। फलस्वरूप स्वतन्त्र भारत में ऐसा संविधान लागू किया गया जो जातिविहीन तथा वर्गविहीन समाज के लिए प्रतिबद्ध था। यहां सोचा गया कि भूमि सुधारों के प्रयासों से सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को समाप्त अथवा कम किया जा सकेगा। इसी दृष्टि से भारत में भूमि सुधार के अनेक प्रयत्न हुए।

भूमि सुधार का अर्थ एवं उद्देश्य (Meaning & Objectives of Land Reforms)

भूमि सुधार (Land Reforms) का अर्थ दो प्रकार से लगाया जाता है : संकुचित व विस्तृत। संकुचित अर्थ में, "भूमि सुधार से अर्थ छोटे कृषक एवं कृषि श्रमिकों के लाभ के लिए भूमि स्वामित्व के पुनः वितरण से है।" लेकिन विस्तृत अर्थ में, "भूमि सुधार से अर्थ किसी संगठन या भूमि व्यवस्था (Land tenures) की संस्थागत व्यवस्था में होने वाले प्रत्येक परिवर्तन से है।" इस प्रकार भूमि सुधार में समस्त कार्य शामिल कर लिए जाते हैं जिनका सम्बन्ध भूमि स्वामित्व (Land Ownership) एवं भूमि जोत (Land holding) दोनों में होने वाले सुधारों से है। इसमें लगान कानून, लगान निर्धारण एवं उनकी वसूलयाबी, मध्यस्थों का उन्मूलन, जोतों की सुरक्षा, अधिकतम व न्यूनतम भूमि सीमा निर्धारण, सहकारी खेती, चकबन्दी, आदि सभी शामिल हैं। भूमि सुधार निम्न उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया जाता है :

- (1) उत्पादन में वृद्धि—भूमि सुधार कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य कृषि उत्पादन को बढ़ाना है। यह उत्पादन वृद्धि सहकारी खेती, चकबन्दी, गहन खेती, आदि के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है।
- (2) सामाजिक न्याय—भूमि सुधार का दूसरा उद्देश्य सामाजिक न्याय है जिससे कि भूमिहीनों एवं वास्तविक काशतकारों को भूमि मिल सके तथा आय में समानता लयी जा सके।
- (3) राजनीतिक उद्देश्य—भूमि सुधार का तीसरा उद्देश्य राजनीतिक है जिसके अन्तर्गत ग्रामीण जन समूह को अपने पक्ष में करने के लिए इस प्रकार की योजनाएं बनाई जाती हैं और कार्यक्रम में परिणत की जाती हैं।

भारत में भूमि सुधारों की आवश्यकता या महत्व (Need or Importance of Land Reforms in India)

भारत में भूमि सुधार की आवश्यकता या महत्व को दर्शाने के लिए निम्न विचार व्यक्त कर सकते हैं :

- (1) कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए—स्वतन्त्रता के समय एवं उसके पश्चात् भारत में कृषि पदार्थों की बड़ी कमी थी। अतः इस बात की आवश्यकता महसूस की गई कि कृषि का उत्पादन बढ़ाने के लिए भूमि सुधार कार्यक्रम लागू किए जाएं।

नियोजित
(2) समझ
साक्षात्कार
(3) सामा
दिलने के लिए
जाए।

(4) गैर-
भूमि सु
क्राण भी पड़ी

'Land Prob
क्रिना ही अ
में वंछित सु
भुधार के कार्य
स्वतन्त्रता के
India a

स्वतन्त्र
काशतकार ए
भाग लगान
नहीं देते थे
उत्पादन भी

प्रथम
था, जबकि
भूमि की उ
कही गई, त
करने पर उ
कृषकों को
जोत कानून
किया जाए
लिए एक
श्रमिकों के
कानूनों के
सिद्धान्तों
भुधार, अ

पि
कार्यक्रम

नियोजित विकास के लिए—देश में नियोजित विकास को बढ़ावा देने के लिए यह समझा गया कि भूमि सुधार किये जाएं।

(2) सामाजिक न्याय एवं समानता के लिए—स्वतन्त्रता के पश्चात् सामाजिक न्याय के लिए यह उचित समझा गया कि आधिक्य भूमि को भूमिहीनों में वितरित कर दिया जाये।

(4) शै-कृषि उद्योगों के विकास के लिए—भारत में भूमि सुधार की आवश्यकता इस उद्योगों के विकास के लिए धन एवं कच्चा माल कृषि से ही मिल सकता है। भूमि सुधारों की आवश्यकता पर बल देते हुए डॉ. राधाकृष्ण मुखर्जी ने अपनी पुस्तक 'Land Problems in India' में लिखा था कि "वैधानिक कृषि तथा सहकारिता को हम अपना ही अपना लें, पूर्ण सफलता हमें तब तक नहीं मिलेगी जब तक कि हम भूमि व्यवस्था सुधार नहीं कर देते।" प्रो. सैमुएलसन (Samuelson) के अनुसार, "सफल भूमि सुधारों के कार्यक्रमों ने अनेक देशों में (साहित्यिक भाषा में) मिट्टी को सोने में बदल दिया है।"

भारत में भूमि सुधार नीति (Land Reforms Policy in India after Independence)

स्वतन्त्रता-प्राप्ति के समय विभिन्न प्रकार की भूमि व्यवस्थाएँ थीं जिसके परिणामस्वरूप किसान एवं भूमि स्वामी के बीच कई मध्यस्थ आ गए थे जो भूमि उपज का एक बड़ा भाग लेते थे, लेकिन फिर भी काश्तकार को प्रतिवर्ष जोतने की गारण्टी नहीं देते थे जिससे भूमि में स्थायी सुधार नहीं हो पाता था। साथ ही खेत के छोटे होने से उत्पादन भी कम होता है। अतः स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पश्चात् सरकार का ध्यान इस ओर गया।

प्रथम योजना में राज्यों द्वारा भूमि सुधार योजना की रूपरेखा बनाने के लिए कहा गया था, जबकि दूसरी योजना में मध्यस्थ किरायेदारों की समाप्ति, काश्तकारी व्यवस्था में सुधार, भूमि की उच्चतम सीमाओं का निर्धारण, चकबन्दी और कृषि व्यवस्था के पुनर्गठन की बातें थीं, लेकिन तीसरी, चौथी व पांचवीं योजना में भूमि सुधार कार्यक्रमों को तेजी से लागू करने पर जोर दिया गया। छठवीं योजना में यह व्यवस्था की गई : (i) जिन राज्यों में भूमिहीन किसानों को मालिकाना हक देने के नियम नहीं हैं वहाँ नियम बनाये जायेंगे। (ii) अधिकतम भूमि कानून लागू होने से जो अतिरिक्त भूमि सरकार के अधिकार में आ गई है उसे वितरित किया जाएगा। (iii) भूमि सम्बन्धी आंकड़ों को संकलित करने एवं उन्हें अद्यतन करने के लिए एक कार्यक्रम लाया जायेगा। (iv) चकबन्दी का कार्यक्रम चलाया जायेगा। (v) भूमिहीन किसानों के मकानों के लिए स्थान की व्यवस्था की जायेगी। सातवीं योजना में वर्तमान भूमि सुधारों को कड़ाई से लागू करने की बात कही गई थी। आठवीं योजना में भूमि सुधार के पांच कार्यक्रमों का पालन करने की बात कही गई है। यह सिद्धान्त है—मध्यस्थों का अन्त, काश्तकारी भूमि, अतिरिक्त भूमि का पुनः वितरण, चकबन्दी व भूस्वामित्व रिकार्ड को अद्यतन करना।

भारत में भूमि सुधार के लिए उठाये गए कदम

(EFFORTS MADE FOR LAND REFORMS IN INDIA)

पिछले वर्षों में भूमि सुधार के काफी प्रयत्न किए गये हैं जिनके फलस्वरूप अग्रकृषि कार्यक्रम लागू किए गये हैं :

में पाई जाती के एक और हीन श्रमिकों त् लोगों का र्त में ऐसा रूढ़ था। यहां गों को समाप्त ल हुए।
Reforms)
: संकुचित व लाभ के लिए से अर्थ किसी चैक परिवर्तन सम्बन्ध भूमि ने वाले सुधारों का उन्मूलन, कबन्दी, आदि
दन को बढ़ाना म से प्राप्त की है जिससे कि नता लयी जा
जैसेके अन्तर्गत बनाई जाती हैं
importance of
न विचार व्यक्त
पश्चात् भारत में गई कि कृषि का

(1) मध्यस्थों एवं जमींदारों का उन्मूलन (Abolition of Intermediaries and Zamindars)

(II) काश्तकारी व्यवस्था में सुधार (Reforms in Tenancy System)

(III) जितों की अधिकतम सीमा-निर्धारण (Ceiling on Holdings)

(IV) कृषि का पुनर्गठन (Reorganisation of Agriculture)—(1) यकत्सी, (2) सहकारी खेती, (3) भूदान, (4) भूस्वामित्व का रिकार्ड।

अब इन सभी की एक-एक करके विस्तृत विवेचना की जाएगी।

(I) **मध्यस्थों एवं जमींदारों का उन्मूलन** (Abolition of Intermediaries and Zamindars)

भूमि सुधार प्रयत्नों में सबसे पहला प्रयत्न मध्यस्थों व जमींदारों की समाप्ति के लिए किया गया। इस सम्बन्ध में चेन्नई में 1948 में; मुम्बई व हैदराबाद में, 1949-50 में; मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश व असम में 1951 में; पंजाब, राजस्थान व उड़ीसा में 1952 में तथा हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक व पश्चिमी बंगाल में 1954-55 में सम्बन्धित अधिनियम पारित किए गए। इन विभिन्न राज्य अधिनियमों के अन्तर्गत अब तक दो करोड़ से अधिक काश्तकारों का राज्य के साथ सीधा सम्बन्ध हो गया है और उनको मालिकाना हक दे दिए गए हैं तथा 60 लाख हेक्टेयर भूमि भूमिहीन कृषकों को वितरित की जा चुकी है।

विभिन्न राज्य सरकारों ने जमींदारी उन्मूलन के लिए जो अधिनियम बनाये थे उनमें निम्न विशेषताएँ थीं :

(1) **अधिकारों का उन्मूलन एवं क्षतिपूर्ति**—जम्मू एवं कश्मीर राज्य को छोड़कर शेष सभी राज्यों में जमींदारों के अधिकारों का उन्मूलन कर दिया गया है और इसके बदले में उनको मुआवजा या क्षतिपूर्ति दी गई है।

(2) **क्षतिपूर्ति का आधार**—जमींदारों को क्षतिपूर्ति का आधार अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग रखा गया; जैसे उत्तर प्रदेश में आधार शुद्ध सम्पत्ति रखा गया था जबकि असम, राजस्थान एवं मध्य प्रदेश में 'शुद्ध आय' था। कुछ राज्यों में बड़े जमींदारों को निम्न दर से छोटे जमींदारों की ऊंची दर से क्षतिपूर्ति की गई। कुछ राज्यों में क्षतिपूर्ति तो एक-सी दर से दी गई, लेकिन छोटे जमींदारों को पुनर्वास हेतु, अतिरिक्त अनुदान दिए गए।

(3) **क्षतिपूर्ति का भुगतान**—क्षतिपूर्ति का भुगतान कुछ राज्यों द्वारा पूर्णतः नकदी में किया गया, जबकि कुछ राज्यों द्वारा नकदी व बाण्डों में। जिन राज्यों में बाण्डों में भुगतान किया गया उन्होंने अपने राज्यों में 'जमींदारी उन्मूलन कोष' की स्थापना की। इस कोष में उस रकम को जमा किया गया जो कृषक ने भूमिधारी काश्तकार बनने के लिए सरकार को दी थी।

(4) **वैयक्तिक कृषि के लिए भूमि रखने की छूट**—विभिन्न अधिनियमों में यह व्यवस्था की गई थी कि जो जमींदार जितनी भूमि को स्वयं जोतते थे उसे उनके पास ही छोड़ देने की छूट थी।

(5) सामान्य भूमि

जो सामान्य भूमि उस पर राज्य सरकार

(6) लगान

उन्मूलन के पश्चात् और लगान देने के

(7) जमींदार

कि प्रत्येक काश्तकार में कार्य करने वा

को उठा सकते

उत्तर प्रदेश में

उत्तर प्रदेश

को एक प्रस्ताव एक समिति पं.

1948 में दे दी को प्रस्तुत किया

जमींदारों ने न्य इस अधिनियम

से राज्य की कृ उत्तर प्रदेश

जिसमें से 3.9 की मात्रा शुद्ध

जिसमें से 90 से भी कम लग

प्रतिशत) ही 2 जमींदार 1,00

लगान देते थे। इस अधि

जो अपने वर्त जाएगा। भवि

लगान की आप फलदायों और

काश्तकार जो की जमीनों क

जमा कराकर भूमि, बगीचों

(3) **सामान्य भूमि पर राज्य सरकारों का अधिकार**—जमींदारी उन्मूलन के पश्चात् गांव सामान्य भूमि (जैसे, बंजर भूमि, वन, हाट की भूमि, चरागाह की भूमि, आदि) बची रहने वाली सरकारी भूमि का अधिकार हो गया।

(4) **लगान देने का दायित्व**—इन अधिनियमों में यह व्यवस्था भी की गई थी कि जमींदारी के पश्चात् काश्तकार या आसामी अपने भूमि पर लगान सीधा ही सरकार को देना शुरू करने की उसकी स्वयं की जिम्मेदारी होगी।

(5) **जमींदारी पुनः पनपने पर प्रतिबन्ध**—इसके लिए अधिनियमों में यह व्यवस्था की गई कि काश्तकार के लिए भूमि को स्वयं ही जोतना अनिवार्य होगा, लेकिन विधवा, फौज आदि को देने वाले सेविवर्ग, बन्दी व रोग से पीड़ित व्यक्ति अपनी भूमि को लगान पर दूसरों को दे सकते हैं।

प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन

उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन में अग्रणी है। उत्तर प्रदेश की विधान ने 8 अगस्त, 1947 को प्रस्ताव पास किया कि जमींदारी का उन्मूलन कर दिया जाए और इस कार्य के लिए समिति प. गोविन्द बल्लभ पन्त की अध्यक्षता में बनाई गई जिसने अपनी रिपोर्ट अगस्त 1949 में दे दी। इस समिति की सिफारिशों के आधार पर एक विधेयक 7 जुलाई, 1949 पारित किया गया जो 16 जनवरी, 1951 को पास हो गया, लेकिन उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में न्यायालयों की शरण ले ली। अन्त में 5 मई, 1952 को सर्वोच्च न्यायालय ने अधिनियम को वैध घोषित कर दिया जिसके फलस्वरूप राज्य सरकार ने 1 जुलाई, 1952 को कृषि जमींदारियों की भूमि का स्वाभित्व अपने हाथ में ले लिया।

उत्तर प्रदेश में 30 जून, 1952 को जमींदारों के पास 4.13 करोड़ एकड़ भूमि थी जो 3.9 करोड़ एकड़ भूमि ही सरकार द्वारा लेने का निश्चय किया गया। क्षतिपूर्ति का शुद्ध आय का 8 गुना रखी गई। जमींदारों की कुल संख्या 30 लाख आंकी गई जो 90 प्रतिशत जमींदार तो केवल नाममात्र के ही जमींदार थे जो 25 रुपये वार्षिक भूमि लगान देते थे। केवल 30,000 जमींदार (अर्थात् कुल जमींदारों की संख्या का 1.5%) ही 250 रुपये वार्षिक से अधिक लगान देते थे। इस 30,000 की संख्या में 5,000 से अधिक 1,000 रुपये तक लगान देते थे तथा 400 ऐसे थे जो 10,000 रुपये से अधिक देते थे। कुल क्षतिपूर्ति 160 करोड़ रुपये आंकी गई थी।

इस अधिनियम ने चार प्रकार के कृषकों को जन्म दिया—(1) **भूमिधर**—वे काश्तकार थे जो वर्तमान लगान का 10 गुना सरकारी खजाने में जमा कर देते थे। (2) **अधिवामी**—वे भूमिधर के भविष्य में उनको लगान नहीं देना होगा, लेकिन मालजुगारी देनी होगी जो वर्तमान में देनी आधी होगी। (3) **सीरदार**—जो काश्तकार 10 गुना जमा न करना चाहें वे सीरदार होंगे और सरकार को वही लगान देते रहेंगे जो जमींदार को देते थे। (4) **अधिवामी**—वे जमींदार जो उप-किसान के रूप में कार्य करते थे अधिवामी कहलायेंगे। इनको अपनी खेती के लिए सीरदार बन सकते थे। (5) **आसामी**—यह वे व्यक्ति थे जो वन भूमि, रहने के लिए सीरदार बन सकते थे। (6) **अधिवामी**—यह वे व्यक्ति थे जो वन भूमि, रहने के लिए सीरदार बन सकते थे। (7) **अधिवामी**—यह वे व्यक्ति थे जो वन भूमि, रहने के लिए सीरदार बन सकते थे। (8) **अधिवामी**—यह वे व्यक्ति थे जो वन भूमि, रहने के लिए सीरदार बन सकते थे। (9) **अधिवामी**—यह वे व्यक्ति थे जो वन भूमि, रहने के लिए सीरदार बन सकते थे। (10) **अधिवामी**—यह वे व्यक्ति थे जो वन भूमि, रहने के लिए सीरदार बन सकते थे।

diaries and

1) चकबन्दी,

diaries and

मासि के लिए 1-50 में; मध्य 1952 में तथा ग्राम पारित किए काश्तकारों का 100 हैं तथा 60

थे उनमें निम्न

तो छोड़कर शेष इसके बदले में

अलग राज्यों में

जबकि असम, को निम्न दर से तो एक-सी दर गए।

पूर्णतः नकदी में पिण्डों में भुगतान की। इस कोष में लिए सरकार को

में यह व्यवस्था भी पास ही छोड़ देने

राजस्थान में जमींदारी उन्मूलन

राजस्थान में काश्तकारी के विभिन्न स्वरूप प्रचलित रहे हैं। इन्हें काश्तकारों के हित में परिवर्तित करने, किराये की राशि निर्धारित करने तथा जमींदारी उन्मूलन के उद्देश्य से बनाये गए, प्रमुख अधिनियम इस प्रकार हैं :

1. राजस्थान भूमि सुधार और जागीरी पुनर्ग्रहण अधिनियम, 1952
2. राजस्थान काश्तकारी उन्मूलन अधिनियम, 1955
3. जमींदारी तथा बिसवादारी उन्मूलन अधिनियम, 1955

भूमि सुधार और जागीरी पुनर्ग्रहण अधिनियम, 1952 की धारा 9 के अन्तर्गत जागीरी क्षेत्र में जो भी किसान था उसको खातेदार घोषित किया गया। जागीरदारों के पुनर्वास के लिए उन्हें स्वयं काश्त की भूमि में आबंटन हेतु प्रावधान धारा 15 व 16 में किए गए। राजस्थान सरकार द्वारा जागीरदारों को उनकी जागीर अधिग्रहण के फलस्वरूप मुआवजा दिया गया। सामन्तों की भूमि का अधिग्रहण करने के साथ-साथ भूदान आन्दोलन भी प्रारम्भ किया गया। सन् 1955 में राजस्थान भूदान यज्ञ बोर्ड का गठन किया गया जिसके अध्यक्ष गोकुल भाई भट्ट थे। कृषि भूमियों के उपयोग के सम्बन्ध में भी एक कानून 1954 में जारी हुआ जिसके अन्तर्गत जिलाधीशों को अधिकार दिए गए कि जिन भूमियों पर दो वर्ष से खेती नहीं हो रही हो, उनके मालिकों को नोटिस दें कि भूमि पर खेती का प्रबन्ध करें और ऐसी भूमि को किसानों को पट्टे पर देने का अधिकार भी तहसीलदार को दिया गया।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (Rajasthan Tenancy Act, 1955) की धारा 15वीं क्रान्तिकारी है क्योंकि इस धारा के अन्तर्गत जो भी किसान अस्थायी तौर पर किसी भूमि पर काश्त (खेती) कर रहा था, 15 अक्टूबर, 1955 से स्वतः ही वह खातेदार हो गया। इसके लिए उसे आवेदन की आवश्यकता नहीं थी। इस प्रकार लाखों किसानों को जो अस्थायी रूप से भूमि पर काबिज थे, काश्त कर रहे थे, स्थायी खातेदार के अधिकार मिल गए।

कृषि भूमि पर सीलिंग सम्बन्धी कानून सन् 1963 से प्रभावी हुआ। पूरे देश में सीलिंग कानून को समान आधार पर बनाने के उद्देश्य से 1973 में एक नया कानून 'राजस्थान कृषि भूमि सीलिंग अधिनियम, 1973' लागू हुआ। इस कानून द्वारा सीलिंग की सीमा दो फसली सिंचित भूमियों के लिए 18 एकड़, एक फसली सिंचित भूमि के लिए 27 एकड़ और बाकी असिंचित भूमियों के लिए 48 एकड़ से 175 एकड़ तक निर्धारित की गई। राजस्थान सीलिंग कानून के अन्तर्गत जो भूमि अधिग्रहण की गई है, वह घटिया किस्म की है। अतः जिन लोगों को ऐसी भूमि आबंटित की जाती है, उन्हें भूमि के विकास के लिए अनुदान भी उपलब्ध कराया जाता है।

धूलू सिंह ने राजस्थान में भूमि-सुधारों सम्बन्धी अपने अध्ययन के आधार पर बताया है, कि मध्यस्थों की समाप्ति और काश्तकारी अधिनियम के क्रियान्वयन की सम्पूर्ण प्रक्रिया ग्रामीण राजस्थान में एक 'सामाजिक क्रान्ति' (Social Revolution) से कुछ भी कम नहीं थी।

1 Dholl Singh, 'A Study of Land Reforms in Rajasthan', Birla College, Pilani¹ quoted by S. M. Shah in his book, 'Rural Development, Planning and Reforms', pp. 110-11.

जमींदारी

(1) श

अन्त जमींदारी

उपहार। (2) मि

अधिकार मि

काम करने

सरकारी आ

में मिलते थे

सत्कार से इ

उनको सरक

में सहायता-

हो गया है

लागू किया

अन्त हो ग

लोकतन्त्र

उन्मूलन से

मिल गया

प्रथा की र

अब न ते

अब वे पै

भूमि—ज

कृषकों मे

आ

और जर्म

है। इस त

(II) का

वि

सैनिक र

या व्यव

करते हुए

और नि

(

कुल उप

योजना

से अधि

बनाये ग

में सिंचि

